DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI: They are not becoming refugees on their own. It is because of the partition. May I know from the hon. Minister why the refugees from West Pakistan were settled comfortably by giving them lands and what has been done for the refugees coming from East Pakistan uptil now? May I know whether, after the Janata Government assumed office, the hon. Minister has gone to any of the refugee camps even for a single day to see what is happening there or what is going on there and what type of lands have been allotted to these people? We are receiving thousands of memoranda from Dandakaranya and other places saying that they have been settled on rough hills where the lands cannot be tilled. (*Interruptions*) May I ask the hon. Minister whether instead of depending on the report which his officers are submitting to him, he will agree to go and visit these places along with some Members of Parliament? Will the hon. Minister agree to visit Dandakaranya, Mana and other places where these refugees have been settled along with some Members of Parliament and not entirely depend on the reports which are being submitted by his officers? Has he ever visited any camps to see that these people are living like pigs?

SHRI KALYAN ROY: He can go to Damascus and other places but he does not get time to go there.

SHRI SIKANDAR BAKHT: This question does not flow from the main question.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA: The question does flow from it. But he has no answer.

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए महिला अध्यापकों के लिए विहित आयु सीमा

*64. **डा० लोकेश चन्द्र** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (i) महिलाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं तथा (ii) महिला अध्यापकों के सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु की विहित सीमायें क्या हैं ;

(ख) क्या महिला अध्यापकों के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†[**Age limit prescribed for lady teachers for entry into teachers' training institutions and Government service**

*64. DR. LOKESH CHANDRA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the age limits prescribed for (i) women for admission to the Government run teachers' training institutions; and (ii) lady teachers for entry into Government service;

(b) whether there is any proposal under Government's consideration to raise the age limit for entry into Government service for the lady teachers; and

(c) if so, what are the details thereof?]

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (ग) जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा शिक्षा मुख्यत: राज्य विषय है तथा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिले तथा सरकारी सेवा में प्रवेश के नियम हर राज्य के अलग-अलग हैं और उनमें समय समय पर संशोधन होता रहता है, अत: मांगी गई सूचना को एकत्र करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा उसके अनुपात में उतना लाभ नहीं होगा ।

†[ ] English translation.

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARAKATAKI): (a) to (c) As the Honourable Member would be aware Education is primarily a State subject and the rules for admission to teachers training institutions and their entry into Government Service vary from State to State and are modfied from time to time and therefore the time and labour that would be spent on collecting the information asked for would not be commensurate with the advantage.]

डा० लोकेश चन्द्र : माननीय मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि शिक्षा इस समय राज्य विषय नही है, वह समवर्ती विषय है, काकरेंट सब्जेक्ट है और संविधान में जब तक संशोधन आप प्रस्तुत नहीं करते तब तक वह कांकरेंट सब्जेक्ट रहेगा, उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता। यह प्रश्न इसलिए उठता है कि जैसे सी०आइ० एस० सेंट्रल इस्टीट्यूट आफ एजुकेशन है उसमें शिक्षिकाओं की प्रवेश की आयु जो निर्धारित की गई है वह 35 वर्ष है। इसी प्रकार से जामिया मिलिया में जो शिक्षिकाएं पढ़ने के लिए जाती है उनके लिए भी आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। परन्तु दिल्ली शिक्षा अधिनियम के अनुसार उनको केवल 30 वर्ष की आयु तक ही दिल्ली में स्थान मिल सकता है। 30 की आयु होने के उपरांत स्थान नहीं मिलता। तो जब मूल रूप से हमारी शिक्षण संस्थाओं में 35 वर्ष है तो कम से कम दो वर्ष तो वे पढ़ेंगी, उसके पश्चात उनकी आयु 35–36 की होगी तब वह शिक्षिकायें बनेंगी। मैं समझता हूं कि यह नियमो में बहुत बडा दोष है। इसको दूर करना चाहिए।

दूसरा प्रश्न यह है कि ये जो सरकारी संस्थाओं में नियम लागू होते हैं यह प्राइवेट संस्थाओं में भी लागू हो रहा है। और दूसरे प्रकार के नियम प्राइवेट संस्थाओं में लागू नहीं होते, लेकिन यह नियम लागू होता है। महिलाओं को बच्चों को देखना पड़ता है, कुछ वर्ष उनको बच्चों में लगाने पड़ते हैं, जब बच्चे बडे हो जाते हैं तब आप उनको शिक्षिकायें बनाते है तो उनके लिए 30 वर्ष की सीमा निर्धारित करना मैं समझता हू बहुत अनुचित है। दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में कोई आयु सीमा नही है। यहां से 30–40 मील दूर जाकर वे शिक्षिकायें बन सकती हैं किन्तु दिल्ली में नही बन सकती है। मेरी दृष्टि में यह समाज विरोधी वृत्ति है, इससे वृत्तिहीनता पैदा होती है।. . .

(Interruptions)

श्री उपसभापति : संक्षेप में पूछिए।

डा० लोकेश चन्द्र : इसलिए मै समझता हूं कि यह नियम महिलाओं की परिस्थिति में संविधान विरोधी है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने कहा कि शिक्षा मुख्यत: राज्य विषय है। 42वें संविधान संशोधन में वह कांकरेंट लिस्ट में आ गया है लेकिन वह 42वां संशोधन हम नही मानते हैं। इसके अलावा बालक और बालिका के बीच उम्र की सीमा में कोई फर्क नही होता है।

There is no discrimination between boy students and girl students with regard to the age limit. That is the position. If the hon. Member wants that something ought to be done with regard to the girls, I cannot give any assurance at the present moment but I may consider this matter.

डा० लोकेश चन्द्र : मंत्री महोदय ने कहा कि हम संपूर्ण संविधान को नही मानते है। संविधान के प्रति उन्होंने शपथ ली है। जब मंत्री महोदय ने शपथ संविधान के प्रति ली है, सदन के अन्दर यह कहना कि हम संविधान के प्रति अपनी शपथ को झूठा करते है, मैं समझता हूं कि मंत्री जी को त्याग-पत्र दे देना चाहिए या फिर ऐसा वक्तव्य सदन के अन्दर नही देना चाहिए।

†[ ] English translation.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि हम यह जानते है कि कांकरेंट लिस्ट में शिक्षा को रख देने से कोई ताकत वह हमको नहीं देना है जब तक कि हम कोई कानून नहीं बनाते है। हमने कोई कानून नहीं बनाया है, इसलिए ऐक्जीक्यूटिव पावर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है।

SHRI KHURSHED ALAM KHAN: Sir, may I know from the hon. Minister whether he would consider giving exemption to the ladies from the age limit in admission or in service because it is a known fact that to ask a question about the age from a lady is rather impertinent?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I will keep that suggestion in view, Sir.

SHRI A. R. ANTULAY: Sir, I would like to put a question to the hon. Minister. I am only concerned with that part of the answer when he said that we know that this has been introduced in the Concurrent List as a result of the 42nd Amendment and that he does not accept that as a Constitutional provision.

12 NOON

I am only asking the question whethere he does or does not accept that as a part of the Constitution and if he does whether he thinks he is bound by it or not? That is my only question.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Sir, the position is very clear. So long as it is a part of the Constitution, we are bound by it. But whether we act upon it or not, that is entirely within our discretion and we are not exercising our discretion so far as matters connected with the Forty-Second Amendment are concerned.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next question, please.

SHRI A. R. ANTULAY: Sir, this is a point . . .

(*Interruption*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are not discussing that matter at present. You can raise a separate discussion. Next question. Mr. Lakshmanan.

Inter-State Movement of Paddy

*65. SHRI G. LAKSHMANAN:†
SHRI BAPURAOJI MAROTRAOJI DESHMUKH:
SHRI SANAT KUMAR RAHA:
SHRIMATI SUSHILA SHANKAR ADIVAREKAR:
SHRIMATI AMARJIT KAUR:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have recently withdrawn all the zonal restrictions on the movement of paddy;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) what are the names of the States which have represented to the Central Government against the decision;

(d) what are the main points contained in their representations;

(e) what steps Government propose to take to assist those States in solving their difficulties in this regard;

(f) whether the State Governments were consulted before taking a decision in the matter; and

(g) whether Government propose to reconsider their decision in the matter?

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri G. Lakshmanan.